ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

18/12/2023

+91 8434931877, +91 7250667974 www.achieversiaspatna.co.in

Orchid Mall, Boring Road, (Opps.- A. N. College) Patna-800001

THE HINDU National

2036 तक वैश्विक कोयले की मांग में 2.3% की गिरावट की संभावना: IEA

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की कोयले पर एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल कोयले का उत्पादन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद, 2026 तक कोयले का उत्पादन घटने वाला है।

रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं

- 2023 में कोयले की वैश्विक मांग 1.4% बढ़कर 8.5 बिलियन टन से अधिक हो गई
- 2023 में EU और USA में मांग में 20% की गिरावट की उम्मीद है, जबकि भारत में 8% और चीन में 5% बढ़ने की उम्मीद है।
- ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन मुख्य कारणों में से एक है, भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को बिजली की बढ़ती मांग के कारण अपना कोयला उत्पादन बढ़ाना पड़ा है।

'काशी तमिल संगमम एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विचार को मजबूत कर रहा है

पीएम मोदी ने रविवार को वाराणसी में दूसरे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया.इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस समागम से एक भारत, श्रेष्ठ भारत का विचार मजबूत हो रहा है. पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे दक्षिण भारत के संतों ने काशी का दौरा किया.

यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, जो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों का जश्न मनाता है, पुष्टि करता है और फिर से खोजता है। समागम की सफलता के लिए बीएचयू और आईआईटी मद्रास जस ने हाथ मिलाया है।

प्रधानमंत्री ने गुजरात में सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया, कहा कि इससे 1.5 लाख और नौकरियां बढ़ेंगी

पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को हीरा कारोबार और आभूषण कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अंतरराष्ट्रीय केंद्र सूरत डायमंड बोर्स (एसडीबी) का उद्घाटन किया।

एसडीबी 67 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बना है.इसमें 15-15 मंजिल की नौ इमारतें हैं।300 वर्ग फुट से लेकर 75000 वर्ग फुट तक के कार्यालयों के साथ, इसका उद्देश्य हीरे के कारोबार को मुंबई से सूरत में स्थानांतरित करना है।

एसडीबी का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "सूरत हीरा व्यवसाय आठ लाख लोगों को रोजगार देता है और नए हीरा बाजार के आने से 1.5 लाख और नौकरियां जुड़ेंगी।“

सूरत भारत में हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का केंद्र है। लेकिन वैश्विक आर्थिक मंदी और रूसी डायमंड पर जी7 के सख्त रुख के कारण उद्योग इस समय संकट का सामना कर रहा है।

पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया. सूरत हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही गुजरात में अब अहमदाबाद, राजकोट, सूरत के नाम पर 3 कार्यशील अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी भी निर्माण चरण में है।

काकरापार में स्वदेश निर्मित यूनिट 4 ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है

गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना (केएपीपी) परियोजना की चौथी इकाई ने नियंत्रित विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी और इस प्रकार रविवार को यह गंभीर हो गई। काकरापार सूरत से लगभग 80 किमी दूर है।

काकरापार संयंत्र की इकाई चार की क्षमता 700 मेगावाट है और यह अब तक निर्मित सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में से एक है। स्वदेश निर्मित रिएक्टर की पिछली उच्चतम क्षमता 540 मेगावाट थी।

साइबर खतरे: केंद्र ने महत्वपूर्ण विभाग के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित ईमेल नेटवर्क स्थापित किया है

साइबर हमलों के मद्देनजर, सरकार ने महत्वपूर्ण मंत्रालयों और विभागों में 10,000 उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित ईमेल नेटवर्क स्थापित किया है, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा है, ईमेल सेवा एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) द्वारा डिजाइन की गई है और इसे ज़ोहो द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।, एक भारत आधारित सॉफ्टवेयर निर्माता।

इन ईमेल में उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ-साथ बायोमेट्रिक्स की चेहरे की पहचान की आवश्यकता होगी।

अंडमान में अनुसूचित जाति की कभी गिनती नहीं की गई: अब एक हाउस कमेटी बैठती है और नोटिस लेती है

भाजपा सांसद किरीट प्रेम भाई सोलंकी की अध्यक्षता वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति ने कहा है कि "अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महत्वपूर्ण उपस्थिति है" जिससे पता चलता है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए उन पर विचार किया जाना चाहिए। सेवाएँ मायने रखती हैं।

अंडमान और निकोबार में दलितों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल कर दिया गया है।

दशकों बाद संसदीय पैनल ने यहां अनुसूचित जाति के सामने आने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए एक विशेष पैनल का आह्वान किया है।

World

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि लीबिया के तट पर प्रवासी जहाज पलटने से 60 से अधिक लोगों के मरने की आशंका है

पश्चिमी लीबिया के ज़ुवारा शहर के पास 86 प्रवासियों को ले जा रही एक नाव पलट गई। ड्रोवोनिग के कारण 61 प्रवासियों की मौत हो गई। ये आंकड़े संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने जारी किये हैं.

लीबिया के माध्यम से भूमध्यसागरीय मार्ग यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे अफ्रीका के प्रवासियों के लिए प्रमुख मार्गों में से एक है।

प्रवासियों के साथ समस्या

कई बार अच्छी नावों की कमी और नावों पर क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने के कारण जहाज पलट जाते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है।

इस वर्ष मध्य यूरोप मार्ग पर 2250 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस वर्ष लगभग 14,900 प्रवासियों को रोका गया और वे लीबिया लौट आए।

कुवैत के अमीर शेख नवाफ को एक सादे समारोह में दफनाया गया

कुवैत के अमीर शेख नवाफ का रविवार को निधन हो गया, उन्हें अलो की अफेयर में दफनाया गया है

दुनिया भर से प्रतिनिधि पहुंचे हैं. भारत से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कुवैत पहुंचे। श्री पुरी प्रधानमंत्री की ओर से शोक पत्र देंगे।

पाठ और प्रसंग

➡ चुनाव आयुक्त के चयन पर

12 दिसंबर को राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्त (ईसी) नियुक्ति विधेयक, 2023 पारित किया। यह सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है।

➡ संविधान क्या कहता है?

अनुच्छेद 324 सीईसी और ईसी की नियुक्ति के बारे में बात करता है। संविधान कहता है कि नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगी।

अब तक नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी।

SC का फैसला?

एक जनहित याचिका दायर की गई थी जो EC और CEC की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ईसी और सीईसी की नियुक्ति के बारे में कोई भी कानून बनाने का निर्देश दिया, और कानून बनने तक पीएम, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति बनाई।

➡ प्रस्तावित कानून क्या प्रदान करता है?

कानून में सीईसी और ईसी को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने का प्रस्ताव है, समिति में पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और पीएम द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं।

सीजेआई को चयन समिति से बाहर करना उन कारणों में से एक है जिसकी आलोचना हो रही है. सरकार से दो सदस्य आलोचना का अन्य बिंदु है।

➡ यूरोपीय संघ के कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम का अवलोकन

नवाचार को बढ़ावा देने और एआई के साथ नैतिक मुद्दों से निपटने के लिए ईयू ने एआई पर अपना स्वयं का अधिनियम लागू किया है, ताकि एआई का उपयोग जिम्मेदार हो।

अधिनियम की ताकत और सीमाएँ

- एआई एप्लिकेशन को अस्वीकार्य से लेकर निम्न तक विभिन्न जोखिम स्तरों में वर्गीकृत किया गया है
- एआई प्रथाएँ जिन्हें अस्वीकार्य माना गया वे हैं: सरकारी उद्देश्यों के लिए सामाजिक क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली।, पूर्वानुमानित पुलिसिंग अनुप्रयोग, और एआई प्रणालियाँ जो व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं जैसे कि काम या शिक्षा में भावनात्मक पहचान प्रणाली,
- इसमें डेवलपर्स को एआई की पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में स्पष्ट निर्देश देने की आवश्यकता है
- चिकित्सा उपकरणों, बायोमेट्रिक पहचान और न्याय और सेवाओं तक पहुंच जैसे उच्च जोखिम वाले एआई अनुप्रयोगों को तीसरे पक्ष की संस्थाओं द्वारा आयोजित मूल्यांकन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।